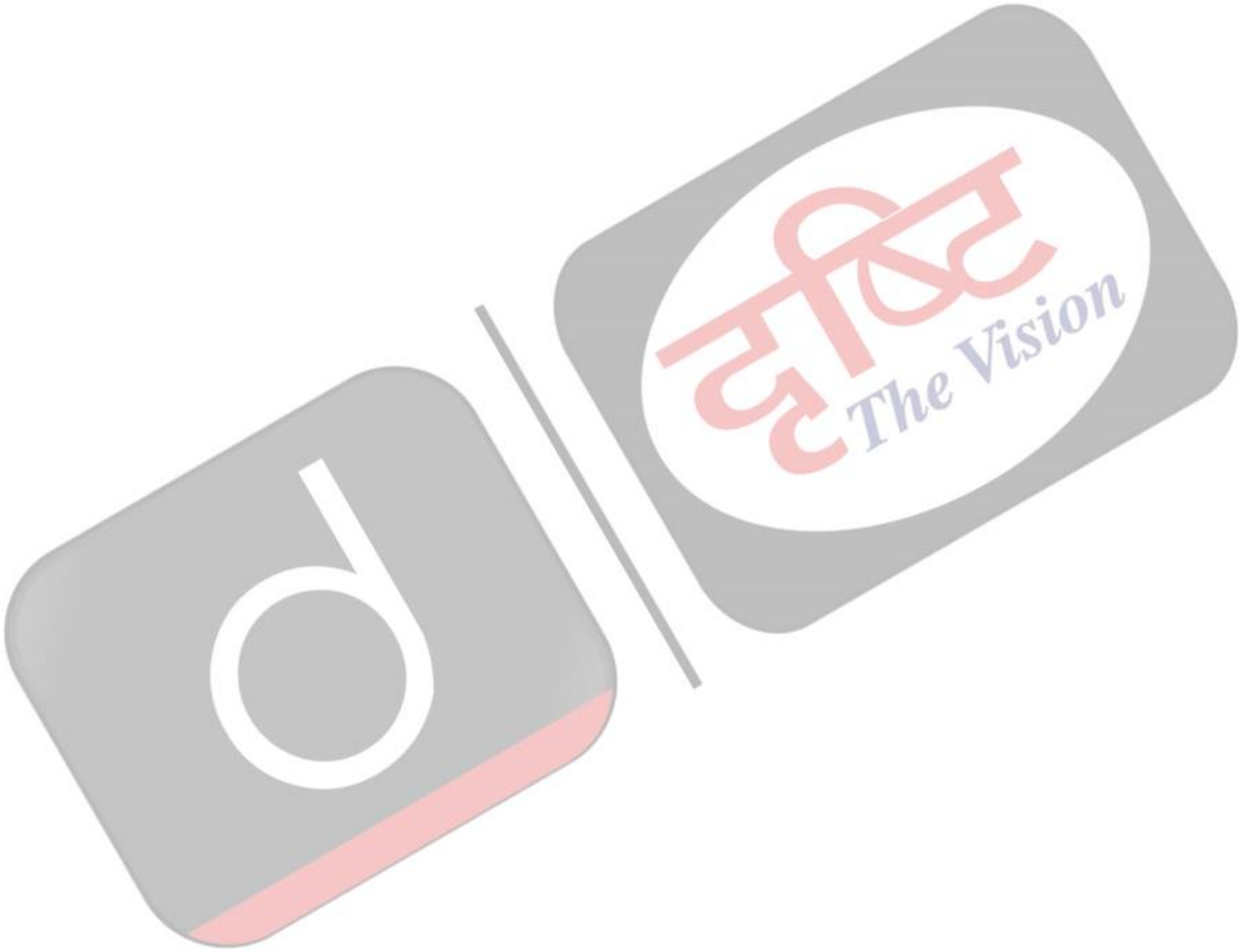




भारत के मुख्य न्यायाधीश





भारत के मुख्य न्यायाधीश (सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख)

CHIEF JUSTICE OF INDIA
(Head of the Supreme Court)



भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश (CJI):

✧ जस्टिस उदय उमेश ललित

अर्हता:

- ✧ भारत का नागरिक हो।
- ✧ निम्नलिखित में से किसी एक अर्हता को पूरा करता हो:
 - ✧ किसी उच्च न्यायालय में या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों में लगातार कम-से-कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो, अथवा
 - ✧ किसी उच्च न्यायालय में या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों में लगातार कम-से-कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, अथवा
 - ✧ राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो।
- ✧ संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिये न्यूनतम आयु-सीमा निर्धारित नहीं की है।
- ✧ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं।

नियुक्ति:

- ✧ CJI की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124 (2) के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- ✧ प्रोटोकॉल के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को CJI के रूप में नामित किया जाता है।
- ✧ सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की सिफारिश के संबंध में आधिकारिक तौर पर मौजूदा CJI द्वारा विधि और न्याय मंत्रालय को सूचित किया जाता है, जिसे आगे प्रधानमंत्री को भेजा जाता है।
- ✧ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सिफारिश पर सलाह देता है और राष्ट्रपति इसकी बाद में नियुक्ति करता है।

भूमिका:

- ✧ राष्ट्रपति और राज्यपालों की शपथ।

- ✧ “मास्टर ऑफ द रोस्टर”, CJI के पास सर्वोच्च न्यायालय में मामलों की सुनवाई के लिये बेंच गठित करने की शक्ति है। CJI तय करता है कि कौन सा न्यायाधीश किस मामले की सुनवाई करेगा और कब करेगा।
- ✧ CJI (सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम के साथ) से राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये परामर्श किया जाता है।
- ✧ CJI संविधान के अनुच्छेद 127 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है।
- ✧ राष्ट्रपति की मंजूरी से CJI दिल्ली से किसी अन्य स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की पीठ स्थानांतरित कर सकते हैं।
- ✧ CJI केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय विवाद को सुलझाने के लिये मध्यस्थ नियुक्त कर सकता है।

हटाए जाने की प्रक्रिया:

- ✧ राष्ट्रपति के आदेश से
 - ✧ संसद द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत एक समावेदन के बाद ही किया जा सकता है।
 - ✧ संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत द्वारा समर्थित (अर्थात उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत से और उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से)।
- ✧ निष्कासन का आधार- सिद्ध कदाचार या अक्षमता (अनुच्छेद 124(4))।

सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2019 में फैसला सुनाया कि CJI का कार्यालय RTI अधिनियम, 2005 के दायरे में आता है।

[और पढ़ें.....](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/chief-justice-of-india-3>

